



Neutral Citation No. -

2026:AHC:59112

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या – 2332 वर्ष 2026

श्रीमती अलीशा और 4 अन्यआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्यप्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अमर जीत सिंह, भुवनेश कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 72

माननीय न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा

1. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री भुवनेश कुमार सिंह और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री राधे श्याम की दलीलें सुनीं तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

2. यह आवेदन अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया है: शिकायत मुकदमा अपराध संख्या 35152/2024, धारा 323, 392, 506 आईपीसी के तहत, पुलिस स्टेशन धामपुर, जिला बिजनौर में, इस प्रार्थना के साथ कि गिरफ्तारी की स्थिति में, याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी बताया गया है कि वर्तमान मामले में घटना की तारीख से एक दिन पहले प्रथम शिकायतकर्ता द्वारा आवेदक संख्या 4 के विरुद्ध वैवाहिक अपराधों का मामला दर्ज किया

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गया था, अर्थात 16.03.2024 को, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 112/2024 है और जिसमें धारा 498-ए, 323, 506 आईपीसी, वैवाहिक संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तीन महीने की देरी के बाद शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें अपराध की तारीख 17.03.2024 बताई गई है। आगे यह भी बताया गया है कि आवेदकों ने कथित तौर पर प्रथम शिकायतकर्ता पर हमला किया और 40,000 रुपये नकद से भरा एक बैग भी लूट लिया। यह भी निवेदन किया गया कि आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और वे जांच एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकतानुसार उपस्थित होंगे। यह कहा गया है कि यदि आवेदकों को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और जांच में सहयोग करेंगे तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।

4. दूसरी ओर, माननीय ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है।

5. शिकायत में लगाए गए आरोप के अनुसार, आवेदकों पर 40,000 रुपये से भरे बैग को लूटने और उस पर हमला करने का आरोप है। आवेदक मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। शिकायत तीन महीने की देरी के बाद दर्ज की गई है। यह भी बताया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत पर निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7. इस मामले में, अग्रिम जमानत से संबंधित कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आवेदकों की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. उपरोक्त मामले में अपराध के लिए अभियोक्ताओं - श्रीमती अलीशा, श्रीमती रशीदा, रुस्तम, श्रीमती शाहनाज़ और शारिक की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



राशि के दो जमानतदारों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:

- (i) अभियोक्ता साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और वे निर्धारित तिथि पर ट्रायल न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उन्हें छूट न दी जाए;
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या त्रादा नहीं करेंगे जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, ताकि उसे न्यायालय या किसी भी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।
- (iii) आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।
- (iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

10. किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर, अभियोजन पक्ष आवेदकों को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

19 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार

सिन्हा)

वीरेंद्र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"